an>

Title:

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे दिल्ली की एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में लगभग 17,000 टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त किये गये हैं। वे 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में चलने वाली सरकार ने यह वायदा किया था कि जब वह अपनी सरकार बनायेंगे तो उनको नियमित करेंगे, ऐसी लॉलीपॉप उनको दी थी। यह केवल टीचरों की बात नहीं है बल्कि डी.टी.सी. कंडक्टर्स, सफाई कर्मचारियों, एम.सी.डी., एन.डी.एम.सी., डी.डी.ए., सभी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोगों से यह वायदा किया गया था कि हम सबको परमानैन्ट करेंगे। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासन काल में उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त गया था, पिछले 6 महीने से टीचर्स इसकी मांग को करते आ रहे हैं। नयी सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। उनकी बात को वह नहीं सुन रही है। उन्हें सचिवालय के अंदर जाने का मौका ही नहीं दे रही है। जो लोग सरकार में चुनकर आये हैं, वे 10 वर्षों से काम करने वाले लोगों की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ नये लोगों को नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर गवर्नर का डायरैक्ट इन्टरफेयरैन्स है क्योंकिएल.जी. दिल्ली सरकार का मुखिया होता है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं केन्द्र सरकार लेफ्टिनैंट गवर्नर से इसमें इंटरफेयर करें और उन टीचर्स एवं ऐसे 1,00,000 कर्मचारियों को स्थायी किया जाये। अगर टीचर्स के साथ ऐसा व्यवहार होगा जो लोगों के मार्गदर्शक होते हैं? भारत की संस्कृति में कहा गया है : -

""गुरु गोविन्द दोहु खड़े, काके लागू पाय,

बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो मिलाय।""

लोगों को भगवान से मिलाने का माध्यम टीचर्स हैं लेकिन उन अध्यापकों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है तो वे आने वाले जेनरेशंस को क्या शिक्षा देंगे? उनके साथ यह अन्याय हो रहा है। इसलिए गवर्नर के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव होना चाहिए कि सरकार ने अस्थायी टीचर्स से जो वायदे किये हैं, उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए, जिससे स्कूल में बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा दी जा सके।

HON. SPEAKER: Actually it is a State matter.